सं0–5/निदे0(छात्र0)–23–151/2016(खण्ड)–

बिहार सरकार

<u>अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग</u>

3098
20.12.17

<u>संकल्प</u>

20 दिसम्बर 2017

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 से विद्यालय छात्रवृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से करने एवं DBT के माध्यम से राशि को सीधे लाभुकों के बैंक खाता में हस्तांतरित करने की स्वीकृति तथा विभागीय संकल्प संख्या–4061 दिनांक–16.05.2016 द्वारा निर्धारित दर पर DBT के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवीकरण एवं नवीन) का संचालन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के स्तर से करने की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवीकरण एवं नवीन) का संचालन शिक्षा विभाग के स्तर से करने की स्वीकृति।

वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित कल्याण विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन किया जाता है, जो निम्नवत् हैः–

(क) विद्यालय छात्रवृत्तिः–

राज्य के सरकारी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में वर्ग–1 से 10 तक में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विद्यालय छात्रवृत्ति से संबंधित राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर की प्रति **परिशिष्ट 1 एवं 2** के रूप संलग्न है।

वर्तमान में विद्यालय छात्रवृत्ति का वितरण छात्रों/छात्राओं की उपस्थिति 75 प्रतिशत या उससे ज्यादा हो तो निर्धारित दर पर छात्रवृति दी जाती है। छात्रों/छात्राओं की उपस्थिति की संख्या शिक्षा विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति की राशि की निकासी कर RTGS/NEFT के माध्यम से संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति के खाता में अंतरण की जाती है। तत्पश्चात् विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय छात्रवृत्ति की संबंधित छात्रों/छात्राओं के खाता में अंतरित की जाती है।

(ख) मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजनाः–

यह योजना वर्ष–2008–09 से प्रारंभ की गई है। वर्तमान में 10वीं की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को ₹8000/– की दर से एवं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को ₹10000/– की दर से प्रदान की जाती है। इसी प्रकार वर्ष–2016–17 से 12वीं की कक्षा में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्राओं को क्रमशः ₹15,000/– एवं ₹10000/– प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

उक्त राशि बिहार के स्थायी निवासी छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उत्तीर्णता के अनुसार RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित की जाती है। वित्तीय वर्ष–2016–17 में निर्गत स्वीकृत्यादेश की प्रति परिशिष्ट–3 के रूप में संलग्न है।

(परिशिष्ट–3)

(ग) प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाः–

(a) राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान् छात्र/छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करने के लिए योजना, गैर योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना संचालित है। इस योजना के तहत् विधिवत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/ संस्थान में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को छात्रवृति की स्वीकृति दी जाती है। इस योजना के तहत् राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है।

(b) संकल्प संख्या–798 दिनांक–25.03.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष–2016–17 से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 11वीं एवं 12वीं वर्ग में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को निर्धारित मापदण्डों के आधार पर छात्रवृत्ति भुगतान की स्वीकृति दी गई है।

(c) विभागीय संकल्प संख्या–4061 दिनांक–16.05.2016 द्वारा निर्धारित दर पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के स्तर से किया जायेगा एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा।

(d) राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका की प्रति परिशिष्ट–4(क) एवं 4(ख) के रूप में संलग्न है।

(परिशिष्ट–4)

अतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को विद्यालय छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना एवं प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का लाभ ससमय पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत मार्गदर्शिका/अनुदेश/मापदण्डों के आधार पर सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिए गए है :–

(i) वित्तीय वर्ष 2017–18 से विद्यालय छात्रवृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से करने एवं DBT के माध्यम से राशि को सीधे लाभुकों के बैंक खाता में हस्तांतरित की जाएगी।

(ii) विभागीय संकल्प संख्या–4061 दिनांक–16.05.2016 द्वारा निर्धारित दर पर DBT के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवीकरण एवं नवीन) का संचालन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के स्तर से करने की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवीकरण एवं नवीन) का संचालन शिक्षा विभाग के स्तर से किया जाएगा।

(iii) उल्लेखित छात्रवृत्ति/मेधावृत्ति योजना के लिए बजट उपबंध एवं उद्व्यय प्राप्त करने तथा प्रावधानित राशि शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने की कार्रवाई अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा की जाएगी।

(iv) विभागीय संकल्प संख्या–4061 दिनांक–16.05.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

2. <u>योजना के लिए आवश्यक निधि का श्रोत</u> :–

<u>बजट–शीर्ष</u>

स्थापना एवं प्रतिव्यय, राज्य स्कीम एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत माँग संख्या–44 में अनुसूचित जाति के लिए मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण उप मुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण एवं अनुसूचित जनजाति के लिए मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण उप मुख्य शीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण से विकलनीय होगा।

3. उपर्युक्त के अनुपालन के क्रम में विहित प्रक्रिया अन्तर्गत सम्यक् जाँचोपरांत छात्रवृति की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

20.12.17

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 5/निदे0(छात्र0)–23–151/2016(खण्ड)– 3098 पटना, दिनांक–20.12.2017

प्रतिलिपि– हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इसे राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभाग को 1500 अतिरिक्त प्रतियां भेजने हेतु अग्रसारित ।

20.12.17

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– 5/निदे0(छात्र0)–23–151/2016(खण्ड)– 3098 पटना, दिनांक–20.12.2017

प्रतिलिपि– हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.12.17

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– 5/निदे0(छात्र0)–23–151/2016(खण्ड)– 3098 पटना, दिनांक–20.12.2017

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.12.17

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– 5/निदे0(छात्र0)–23–151/2016(खण्ड)– 3098 पटना, दिनांक–20.12.2017

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.12.17

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– 5/निदे0(छात्र0)–23–151/2016(खण्ड)– 3098 पटना, दिनांक–20.12.2017

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय को सूचनार्थ प्रेषित।

20.12.17

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– 5/निदे0(छात्र0)–23–151/2016(खण्ड)– 3098 पटना, दिनांक–20.12.2017

प्रतिलिपि– सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली /सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.12.17

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– 5/निदे0(छात्र0)–23–151/2016(खण्ड)– 3098 पटना, दिनांक–20.12.2017

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

20.12.17

सरकार के सचिव ।

परि०-1

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

स0सं0-4/निदे0-छात्रवृत्ति(विविध)-181-10/2010- 282

संकल्प

पटना, दिनांक- 11-2-2011

विषय- अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए संचालित छात्रवृत्ति के दरों में दिनांक-1/4/2011 से संशोधित दर की स्वीकृति।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्ग- I से IV, वर्ग- V से VI, तथावर्ग-VII से X मे अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को क्रमश 15/- रू0, 30/-रू0, एव 55/- प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। साथ ही मुशहर/ भुंइया छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ग I से VI के लिए 30/-रू0 प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।

इसके अलावा तकनीकि छात्रवृत्ति वर्ग- I से X तक (150/-रू0 प्रति माह 10 माह के लिए), छात्रावासी छात्रवृत्ति छात्र/छात्राओं के लिए (80/- प्रति माह 12 माह के लिए) कोच एव खिलाडी के लिए, कीडा छात्रवृत्ति (200/ रू0 प्रति माह 6 माह के लिए) दी जाती है ।

2- छात्रवृत्ति के ये दर अंतिम वर्ष- 1990-99 में संशोधित किया गया था। लगातार बढती मुद्रस्फीति की दर एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के छीजन दर को देखते हुए तथा इस वर्ग के छात्र/छात्राओं को पढाई के प्रति आकर्षित करने के लिए निम्न तालिका के कॉलम-4 के अनुसार छात्रवृत्ति के दरो में संशोधन किया जाता है। छात्रवृत्ति के संशोधित दर दिनांक- 01.4.2011 से प्रभावि होगें

क्र0	योजना का नाम	वर्तमान दर (प्रति माह 12 माह के लिए)	दिनांक-01/4/2011 से संशोधित दर (प्रति माह 12 माह के लिए)
1	2	3	4
1	विद्यालय छात्रवृत्ति-वर्ग-I से IV	15/-	50/-
2	विद्यालय छात्रवृत्ति-वर्ग-V से VI	30/-	100/-
3	विद्यालय छात्रवृत्ति-वर्ग-VII से X	55/-	150/-
4	मुशहर/भुंइया छात्रवृत्ति-वर्ग-I से VI*	30/-	100/-
5	तकनीकि छात्रवृत्ति	150/- प्रति माह	500/- प्रति माह 10 माह के लिए।
6	छात्रावासी- वर्ग- I से X	80/- प्रति माह 12 माह के लिए।	250/- प्रति माह 12 माह के लिए।
7	कीडा छात्रवृत्ति (कोच एव छात्र/छात्रा प्रत्येक के लिए)	200/- प्रति माह 6 माह के लिए।	700/- प्रति माह 6 माह के लिए।

*ऐसे मुशहर/भूईयां छात्र/छात्रा जिन्हें मुशहर/भुंइया छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा उन्हें साधारण अनु0जाति छात्रवृत्ति देय नहीं होगा।

Sankalp stipend rate revision 2010-11

3- वर्ग I से X तक सरकारी विद्यालयों, स्थायी मान्यता प्राप्त एवं अराजकीय प्रस्वीकृत विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी छात्र/छात्राओं को यह छात्रवृत्ति देय होगी। इस योजना के तहत कोई आय सीमा नहीं होगी।

4- अपरावत्त व्यय माँग संख्या 44 के तहत मुख्य शीर्ष 2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण के अन्तर्गत विकलनीय है।

5- छात्रवृत्ति के इन दरों में प्रत्येक दो वर्ष में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव में योजना प्राधिकृत समिति की सहमति प्राप्त है।

6- सभी अर्हता प्राप्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बिहार राज्य के निवासी सभी छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति योजना के तहत आच्छादित किया जायेगा।

7- छात्रवृत्ति के संशोधित दरों योजना प्राधिकृत समिति की अनुशंसा एवं मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी जन प्रतिनिधियों/जनसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित की जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

10/2/11

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 4/निदे0-छात्रवृत्ति(विविध) 181-10/2010- 282 पटना, दिनांक 11-2-2011

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/2

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 4/निदे0-छात्रवृत्ति(विविध)-181-10/2010 282 पटना, दिनांक 11-2-2011

प्रतिलिपि- हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को [illegible] राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभाग को 1500 अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने हेतु अग्रसारित।

10/2

सरकार के सचिव

4/निदे0-छात्रवृत्ति(विविध) 181-10/2010 282 पटना, दिनांक 11-2-2011

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक [illegible] प्रेषित।

सरकार के सचिव

परि० - 2

CENTRALLY-SPONSORED

SCHEME OF

PRE MATRIC SCHOLARSHIP

FOR

SCHEDULED CASTE STUDENTS

GUIDELINES

सत्यमेव जयते
Government of India

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA
JULY, 2012

CENTRALLY-SPONSORED SCHEME OF PRE MATRIC SCHOLARSHIP TO THE SCHEDULED CASTE STUDENTS

(EFFECTIVE FROM 01-07-2012)

CONTENTS

Sl. No.	Topic	Page No.
1.	Background	3
2.	Objectives	3
3.	Scope	3
4..	Conditions of Eligibility	3
5.	Annual Parental/Guardian's Income	4
6.	Value of Scholarship	4
7.	Selection of Candidates	6
8.	Duration and Renewal of Awards	6
9.	Payment of Scholarship	6
10.	Conditions for continuation of the Award	6
11.	Publicity of the Scheme & Inviting Applications	7
12.	Application Procedure	7
13.	Mode of Disbursal of Scholarship	8
14.	Pattern and Conditions of Central Assistance	8
15.	Transfer of Committed Liability to States/UTs	9
16.	Procedure for claiming and Release of Central Assistance	9
17.	Monitoring	9
18.	Change in the Provisions of the Scheme	10

SCHEME OF PRE MATRIC SCHOLARSHIPS TO THE SCHEDULED CASTE STUDENTS

(EFFECTIVE FROM 01-07-2012)

1. BACKGROUND

Article 46 of Part IV ("Directive Principles of State Policy") of the Constitution enjoins upon the State to promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Article 38(2) of the same Part also enjoins upon the State to minimize inequities in income and to endeavour to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations.

2. OBJECTIVES

Objectives of the scheme are:

(a) To support parents of SC children for education of their wards **studying in classes IX and X** so that the incidence of drop-out, especially in the transition from the elementary to the secondary stage is minimized, and

(b) To improve participation of SC children in classes IX and X of the pre-matric stage, so that they perform better and have a better chance of progressing to the post-matric stage of education.

3. SCOPE

Scholarship under the Scheme will be available for studies in India only and will be awarded by the Government of the State/Union Territory to which the applicant belongs i.e. where he is domiciled.

4. CONDITIONS OF ELIGIBILITY

(i) Student should belong to Scheduled Caste.

(ii) His/ her Parent/Guardian's income should not exceed Rs. 2 lakh per annum.

(iii) She / he should not be getting any other Centrally-funded Pre-Matric Scholarship.

(iv) She/ he should be a regular, full time student studying in a Government School or in a School recognized by Govt. or a Central/State Board of Secondary Education.

(v) Scholarship for studying in any class will be available for only one

year. If a student has to repeat a class, she / he would not get scholarship for that class for a second (or subsequent) year.

5. ANNUAL PARENTAL/GUARDIAN'S INCOME

Scholarships will be paid to the students whose parents/guardians' income from all sources does not exceed Rs. 2,00,000/- (Rupees two lakh only) per annum.

NOTE 1: So long as either of the parents is alive, only income of the parents, as the case may be, from all sources has to be taken into account only and of no other member even though they may be earning. In the form of income declaration, income is to be declared on this basis. Only in the case where both the parents have died, the income of the guardian who is supporting the student in his/her studies has to be taken. Such students whose parent's income is affected due to unfortunate death of one of earning parents and resultantly comes within the income ceiling prescribed under the scheme, shall become eligible for scholarship, subject to their fulfilling other conditions of eligibility, from the month in which such sad incidence takes place. Applications for scholarships from such students can be considered even after lapse of last date of receipt of applications, on compassionate grounds.

NOTE 2: House rent allowance received by the parents of a student shall be exempted from the computation of 'income' if the same has been permitted to be exempted for the purpose of Income tax.

NOTE 3: Income certificate is required to be taken once only i.e. at the time of admission to courses which are continuing for more than one year.

6. VALUE OF SCHOLARSHIP

The value of scholarship includes the following for complete duration of the course:-

(i) **scholarship and other grant,**
(ii) **additional allowance for students with disabilities studying in private un-aided recognized Schools.**

The details are as follows:

Rates of scholarship and other grant will be as follows:

Item	Day Scholars	Hostellers
Scholarship (Rs. p.m.) (for 10 months)	150	350
Books and Ad hoc Grant (Rs. p.a.)	750	1000

(ii) Additional Allowances for SC students with disabilities studying in private unaided Schools

Under the Centrally-sponsored Scheme of 'Inclusive Education of the Disabled at Secondary Stage' (IEDSS) implemented by the M/o HRD, assistance @Rs.3000/- p.a. is already being given under its "Student Oriented Component" to students with disabilities studying at the Secondary stage in Govt., local body and Govt. aided schools. However, students in un-aided schools are not covered under IEDSS. Therefore, SC students with disabilities , studying in classes IX & X in private un-aided recognized schools, will be eligible for allowances under this Scheme, as follows:

Allowances for students with disabilities studying in Private un-aided Schools	Amount (In Rs.)
(i) Monthly Reader Allowance for Blind students	160
(ii) Monthly Transport Allowance for students with disabilities (as defined in the Persons with Disabilities Act 1995), if such students do not reside in the hostel which is within the premises of the Educational Institution.	160
(iii) Monthly Escort Allowance for Severely Disabled (i.e. with 80% or higher disability) Day Scholars/Students with low extremity disability	160
(iv) Monthly Helper Allowance admissible to any employee of the hostel willing to extend help to a severely orthopaedically handicapped student residing in the hostel of an Educational Institution who may need the assistance of a helper.	160
(v) Monthly Coaching Allowance to Mentally Retarded and Mentally ill Students	240

Note: The disability as defined under the Persons with disabilities (equal opportunities, Protection of rights and full participation Act, 1995) Act has to be certified by competent medical authority of the State Govt./UT Administration

7. SELECTION OF CANDIDATES

(i) All eligible Scheduled Caste candidates will be given scholarships as prescribed in this Scheme.

(ii) Candidates belonging to one State but studying in another State will be awarded scholarships by the State to which they belong and will submit their applications to the competent authority in that State.

8. DURATION AND RENEWAL OF AWARDS

(i) The scholarship will be payable for 10 months in an academic year.

(ii) The award once made will continue subject to good conduct and regularity in attendance. It will be renewed for Class X after the student passes Class IX.

9. PAYMENT OF SCHOLARSHIP

(i) Scholarship is payable from 1st April or from the month of admission, whichever is later, to the month in which the examinations are completed, at the end of the academic year (including scholarship during holidays), provided that if the scholar secures admission after the 20th day of a month, the amount will be paid from the month following the month of admission.

(ii) In case of renewal of scholarship, it will be paid from the month following the month upto which scholarship was paid in the previous year.

(iii) The Government of the State/Union Territory Administration, to which they belong, in accordance with the procedure laid down by them in this regard, will pay the scholarship money to the selected students.

10. CONDITIONS FOR CONTINUATION OF THE AWARD

(i) The scholarship is dependent on the satisfactory progress and conduct of the student. If it is reported by the Head of the Institution/School at any time that a student has by reasons of his/her own act of default failed to make satisfactory progress or has been guilty of misconduct such as resorting to or participating in strikes, irregularity in attendance without the permission of the authorities concerned etc., the authority sanctioning the scholarship may either cancel the scholarships or stop or withhold further payment for such period as it may think fit.

(ii) If a student is found to have obtained a scholarship by false statements, his/her scholarship will be cancelled forthwith and the amount of the scholarship paid will be recovered, at the discretion of the concerned State Government/ UT Administration. The student concerned will be blacklisted and debarred for scholarship in any scheme forever.

(iii) A student is liable to refund the scholarship amount at the discretion of the State Government/ UT Administration, if during the course of the year, the studies for which the scholarship has been awarded, is discontinued by him/her.

11. PUBLICITY OF THE SCHEME & INVITING APPLICATIONS

11.1 The Scheme will be implemented through State Governments/U.T. Administrations. All the State Governments/UT Administrations will, at the appropriate time, suitably publicise the Scheme and invite applications by issuing an advertisement in local language, in the leading newspapers of the State and through their respective websites and other media outfits. The applicant should submit the completed application to the prescribed authority, as mentioned below before the last date prescribed for receipt of applications.

11.2 State Govt. would prescribe a suitable application form in the local language and place it on its websites. School authorities will get these forms filled by the eligible students and send them to Block / District level authorities. State Governments/UT Administrations will delegate powers to sanction scholarships under the scheme to appropriate District / Block level authorities/ Heads of Institution, as appropriate.

12. APPLICATION PROCEDURE

(i) An application for scholarship should comprise:

(a) One copy of the application for scholarship in the prescribed form (separate application forms as have been prescribed for 'fresh' and renewal scholarship by concerned States/UTs).

(b) One copy of the passport size photograph with signatures of the student thereon (for fresh scholarship).

(c)A certificate (in original) of Caste duly signed by an authorized Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.

(d)An income declaration by the self-employed parents/guardians, stating definite income from all sources by way of an affidavit on non-judicial stamp paper. Employed parents/guardians are required to obtain income certificate from their employer and for any additional income from other sources, they would furnish declaration by way of an affidavit on non-judicial stamp paper.

(e) A receipt in acknowledgement of the scholarship in the previous year on the form attached to the application only duly counter-signed by the Head of the Institution/School concerned, if the applicant was in receipt of a scholarship under this scheme in the preceding year.

(ii) Application complete in all respects, shall be submitted to the Head of the Institution/School, being attended or last attended by the candidates and shall be forwarded by the Head of Institution, after scrutiny and with his

recommendation, to the sanctioning authority, mentioned in para 11.2.

13. MODE OF DISBURSAL OF SCHOLARSHIP

In order to ensure timely and correct payment of scholarship amount to the beneficiaries, State Governments/UT administrations should ensure payment of scholarship through their accounts in post offices/banks. All State Govts/UT Administrations will implement a computerized management system of scholarships, including 'e-payment' system.

14. PATTERN AND CONDITIONS OF CENTRAL ASSISTANCE(CA)

14.1 The Scheme is Centrally Sponsored Scheme and implemented by the State Governments and Union Territory Administrations, which will receive 100% central assistance from Government of india for expenditure under the Scheme, over and above their Committed Liability. The level of Committed Liability of a State Government/Union Territory Administration for a year will be equivalent to the level of actual expenditure incurred by them under the Scheme during the terminal year of the previous Five Year Plan Period, and will be required to be borne by them by making provision in their own budget.

14.2 Many States/UTs are presently implementing Pre-matric Scholarship Scheme of some kind for SC students, from their own resources. If a State Govt. is already giving pre-matric scholarship to SC students of classes IX-X, it will have to either:

i) continue to provide scholarship at that rate, over and above the Scholarship under the proposed CSS,

or

ii) if it chooses to reduce its own expenditure on its Scheme, utilize the saving so effected only on other educational programmes for SCs.

14.3 Upto 1.5 % of total Central expenditure towards Scholarship, would, be utilized on administrative expenditure, Management, Monitoring & Evaluation etc. The funds would be utilized for this purpose, by the Central Govt. or it would be released to States/UTs, over and above the Scholarship amount, on the basis of proposals received from them in this regard. However, no new posts would be created under this component.

15. TRANSFER OF COMMITTED LIABILITY TO STATEs/UTs

As per the existing practice, committed liability in such Schemes gets transferred to the States/UTs during the first year of the succeeding plan period. Since this Scheme has been introduced during the last year of XI Plan i.e. 2011-12. committed liability would be transferred, for the first time, to State Govts/UT Admns at the end of XII Five Year Plan i.e. w.e.f. 1.4.2017.

16. PROCEDURE FOR CLAIMING AND RELEASE OF CA

16.1 CA will be released to the States/UTs, in two installments. First installment of CA would be released on ad-hoc basis, as far as possible, during the second quarter of the year (April- June) subject to satisfactory utilization of Central assistance, released in the past, if any. State Governments/UT Administrations will be expected to submit their complete proposals for CA under the Scheme by 30th September each year which would be released to them, subject to fulfillment of all the conditions, by 31st December. Next year's claim will have to be accompanied with a Utilization Certificate along with Audited Statements for the previous year's CA. Unspent or unaccounted for balance, if any, from the previous year's grant will be adjusted, while releasing the next year's grant.

16.2 State Governments/ UT Administrations will be expected to ensure timely and regular disbursal of scholarships to students through Bank /Post office accounts, preferably on monthly basis. Pending release of CA, the scholarships would be expected to be paid out of the State Budget, against which reimbursement can be claimed. <u>In no case the disbursal of the scholarship to students should be held up due to any delay in the release of CA</u>.

17. MONITORING

State Governments and Union Territory Administrations implementing the scheme will:

i) furnish data of beneficiaries and expenditure under the scheme, to Government of India, regularly in the Quarterly Progress Reports whose proforma would be separately prescribed. Financial assistance given under the scheme shall not be utilized for any other purpose.
ii) make beneficiaries database which may be integrated with UIDAI by (a) embedding Aadhaar numbers (UID numbers) in it, (b) using the UIDAI enabled bank account (UEBA) for crediting the scholarships and (c) using the UIDAI authentication services for beneficiary identification.
iii) ensure that an institution-wise list of awardees, with necessary particulars, for award of scholarships is displayed on the web-site of NIC at District level.

iv) designate Grievance Redressal Officers (GROs) at the State and District levels to redress students' scholarship-related grievances.

18. CHANGE IN THE PROVISIONS OF THE SCHEME

The provisions of this Scheme can be changed at anytime at the discretion of the Government of India.

<u>**FORMAT FOR STATE GOVERNMENTS/UTs FOR SEEKING CENTRAL ASSISTANCE UNDER SCHEME OF PRE-MATRIC SCHOLARSHIP FOR SC STUDENTS**</u>

No. 11014/28/2007-SCD-V
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
(SCD-V)

Shastri Bhavan, New Delhi
Dated: 08.06.2011

To

Secretaries in charge of SC Welfare, All States/UTs

Subject: Changes in the centrally sponsored scheme of Pre-Matric Scholarship to children of those engaged in 'unclean' occupations.

Reference: The Ministry's letter of even number dated 21.01.2009.

Madam/Sir,

The Government of India is implementing the Scheme of Pre-Matric Scholarship to children of those engaged in 'unclean' occupations since 1977-78. The scheme aims to provide financial assistance for pre-matric education to children of the following target groups, viz. (i) scavengers (ii) sweepers having traditional links with scavenging, (iii) tanners, and (iv) flayers. Under the scheme, 100% central assistance is provided to State Governments/UT Administrations from the Government of India for the total expenditure under the Scheme, over and above their respective Committed Liability. The level of Committed Liability of respective State Governments/Union Territory Administrations for a year is equivalent to the level of actual expenditure incurred by them under the scheme during the terminal year of the last Five Year.

2. Regulations governing the Scheme were communicated to States/UTs vide this Ministry's letter no.11014/28/2002-SCD-V dated 30.10.2003. These were last modified w.e.f.1.4.2008 and communicated to States/UTs vide this Ministry's letter of even number dated 21.01.2009.

3. The above Scheme has now been further partially modified so as to revise its '**Object**' and '**Conditions of eligibility**', in such a manner as to do away with the condition which restricts the Scholarship to the Children of only **existing** manual scavengers.

4. The changes, **which will come into force with effect from 1.7.2011**, are summarized in the table below:

Title/para no. of the Scheme	Existing Provision	Revised Provision
1. Object	The object of the scheme is to provide financial assistance to enable the <u>children of scavengers of dry latrines, tanners, flayers and sweepers who have traditional link with scavenging</u> to pursue pre-matric education.	The object of the scheme is to provide financial assistance to **children whose parents/guardian belong to one of the following categories, to pursue Pre-matric education : -** **i) Persons who are either presently engaged in manual scavenging <u>or</u> were so engaged upto or after 1.1.97 or the date on which the " The Employment of manual scavengers and construction of Dry latrines (Prohibition) Act 1993" came into force in their State/UT, whichever is earlier;** **ii) Tanners; and** **iii) Flayers.** **Note 1:-** "Manual scavenging" in this Scheme will mean as defined in Sec. 2(j) of the ."The Employment of manual scavengers and construction of Dry latrines (Prohibition) Act 1993" **Note 2:-** "Presently engaged in manual scavenging" would include those who may be cleaning human excreta, on a regular basis, either from dry latrines or drains, sewers, septic tanks, manholes etc.
2.Conditions of eligibility	i) Scholarship will be admissible to the children of Indian Nationals who irrespective of their religion, <u>are actively engaged in</u>	i) Scholarship will be admissible to the children/wards of Indian Nationals who, irrespective of their religion are:

	scavenging of dry latrines, ~~and~~ other 'unclean' occupations i.e. tanning and flaying only, which are traditionally considered 'unclean'.	a) **either presently engaged in manual scavenging or were so engaged upto or after 1.1.97 or the date on which the "The Employment of manual scavengers and construction of Dry latrines (Prohibition) Act 1993" came into force in their State/UT, whichever is earlier;** b) **presently engaged in Tanning and/or Flaying.**
	ii) It is not possible to draw a line of demarcation between sweepers and scavengers since most of the sweepers are doing the job of scavenging. Hence, the benefit of this scheme will be available to the children of those sweepers only who have traditional links with scavenging.	**Deleted.**
	iii) In rural areas, children of all those who are actually engaged in scavenging of dry latrines, tanning and flaying will be covered.	**Deleted**
	(iv) Children who are born to parents who are not engaged in such occupations, but have been adopted by such person will be eligible for scholarship only after a lapse of three years from the date of such adoption provided that they have been living with the adopted parents since the date of such adoption. Such children will be eligible only if their parents furnish such certificates (such as of proof	(ii) Children who are born to parents who are not engaged in such occupations, but have been adopted by such person **(as mentioned in sub para 2(i) above)** will be eligible for scholarship only after a lapse of three years from the date of such adoption provided that they have been living with the adopted parents since the date of such adoption. Such children will be eligible only if their parents furnish such certificates (such as

	of their occupation, date of adoption etc.) as may be required by the concerned State Government/Union Territory administration.	of proof of their occupation, date of adoption etc.) as may be required by the concerned State Government/Union Territory administration.
	(v) A certificate should be obtained from the candidates each year to the effect that at least one parent is still engaged in an 'unclean' occupations as defined in the object of the scheme and para 2(i) and (iv) above.	**(iii) A certificate should be obtained from the eligible candidates as follows:** **a) From Children/wards mentioned in sub- para 2(i)(a): only once, at the time of their first application/renewal, as the case may be, of Pre-matric Scholarship, after the coming into force of this revision (of 2011), to the effect that at least one parent belongs to the relevant categories;** **b) From Children/wards mentioned in sub- para 2(i)(b): every year, to the effect that at least one parent is currently engaged in tanning and/or flaying.**

A copy of the revision of regulations of the Scheme, incorporating the above changes is also enclosed **(Annexure).**

5. State Governments/UT Administrations are requested to please widely publicise the above changes and send a proposal for Central assistance for the year 2011-12, in the light of the above revision of the Scheme, so as to reach the undersigned, **not later than 15th July, 2011.**

Yours faithfully

(Ganga Kumar)
Deputy Secretary
Tel: +91-11-23070801
Email: kumar.ganga@nic.in

(22)

Copy for information to:-

1. PS to Minister (SJ&E)
2. PS to Minister of State (SJ&E)
3. PS to Secretary (SJ&E)/PS to Spl. Secretary(SJ&E)
4. Secretary, NCSC/NCSK
5. JS(SCD &Parliament)/JS(SD & Adm)/JS(DD)/JS(BC)/JS&FA/ DDG/Economic Adviser.
6. All Ministries/Departments of Govt. of India
7. All DS/Directors, M/o SJ&E
8. All Sections of SCD Division
9. B&C Section, M/o SJ&E
10. PIO, M/o SJ&E, PIB, Ministry of Information and Broadcasting, Shastri Bhavan, New Delhi.
11. NIC, M/o SJ&E to place on Ministry's website.

(23)

बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0- 5/निदे0(मेधावृत्ति)-61-31/2014(खण्ड)- 96

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक - 13.02.17

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में "मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति मेधा वृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2016 में 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं को वृत्तिका योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र/छात्रा को क्रमशः ₹10,000/- (दस हजार रू0) एवं ₹8000/- (आठ हजार रू0) तथा इंटर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्राओं को वृत्तिका योजना के अन्तर्गत प्रति छात्राओं को क्रमशः ₹15,000/- (पन्द्रह हजार रू0) एवं ₹10000/- (दस हजार रू0) की दर से वृत्तिका के रूप में देने हेतु मैट्रिक उत्तीर्ण के लिए अनु0 जाति मद में ₹5752.52 लाख (सनतावन करोड़ बावन लाख बावन हजार रू0), अनु0 जनजाति मद में ₹674.24 लाख (छः करोड़ चौहत्तर लाख चौबीस हजार रू0) तथा इंटर उत्तीर्ण के लिए अनु0 जाति मद में ₹2528.35 लाख (पचीस करोड़ अठाईस लाख पैंतीस हजार रू0), अनु0 जनजाति मद में ₹376.35 लाख (तीन करोड़ छिहत्तर लाख पैंतीस हजार रू0) अर्थात कुल ₹9331.46 लाख (तिरानवे करोड़ एक्कतीस लाख छियालीस हजार रू0)मात्र की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

2-वित्तीय वर्ष 2016-17 में "मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति मेधा वृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2016 में 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं को वृत्तिका योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र/छात्रा को क्रमशः ₹10,000/- (दस हजार रू0) एवं ₹8000/- (आठ हजार रू0) तथा इंटर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्राओं को वृत्तिका योजना के अन्तर्गत प्रति छात्रा को क्रमशः ₹15,000/- (पन्द्रह हजार रू0) एवं ₹10000/- (दस हजार रू0) की दर से वृत्तिका के रूप में देने हेतु सलंग्न-1 एवं 2 के अनुसार मैट्रिक उत्तीर्ण के लिए अनु0 जाति मद में ₹5752.52 लाख (सनतावन करोड़ बावन लाख बावन हजार रू0), अनु0 जनजाति मद में ₹674.24 लाख (छः करोड़ चौहत्तर लाख चौबीस हजार रू0) तथा इंटर उत्तीर्ण के लिए अनु0 जाति मद में ₹2528.35 लाख (पचीस करोड़ अठाईस लाख पैंतीस हजार रू0), अनु0 जनजाति मद में ₹376.35 लाख (तीन करोड़ छिहत्तर लाख पैंतीस हजार रू0) अर्थात कुल ₹9331.46 लाख (तिरानवे करोड़ एक्कतीस लाख छियालीस हजार रू0)मात्र की स्वीकृति दी जाती है।

3- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए उपबंधित राशि एवं उद्व्यय के आलोक में राज्य योजना मांग सं0-44 के अन्तर्गत अनु0 जाति के लिए आय-व्ययक मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-0107-शिक्षा-3401-छात्रवृत्ति/वजीफा-विपत्र कोड-P2225012770107 राज्य योजना स्कीम कोड-SST-5461 तथा अनु0 जनजाति के लिए मांग सं0-44 के अन्तर्गत आय-व्ययक मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-277-शिक्षा-0101-शिक्षा-3401-छात्रवृत्ति/वजीफा-विपत्र कोड-P2225022770101 राज्य योजना स्कीम कोड-SST-5461 के अधीन बजट उपबंध से राशि वहन किया जायेगा।

4- यह राशि बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उत्तीर्णता के अनुसार सम्बंधित छात्र/छात्रा को उपलब्ध कराया जाएगा।

5- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त होंगे। साथ ही जिला पदाधिकारी अपने स्तर से पूरी प्रक्रिया का अनुश्रवण करते हुए त्रुटिरहित मेधावृत्ति वितरण सुनिश्चित करेंगे।

संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी वर्ष-2016 में 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं को वृत्तिका योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र/छात्रा को क्रमशः ₹10,000/- (दस हजार रू0) एवं ₹8000/- (आठ हजार रू0) तथा इंटर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्राओं को वृत्तिका योजना के अन्तर्गत प्रति छात्रा को क्रमशः ₹15,000/- (पन्द्रह हजार रू0) एवं ₹10000/- (दस हजार रू0) की दर से जाति प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र तथा अंक पत्र के जांचोपरांत उचित पहचान पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर एक मुश्त राशि का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगे।

-8-

जिला कल्याण पदाधिकारी निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार बिहार, पटना को उपलब्ध करायेगें तथा एक प्रति विभाग को भी देंगे।

6– राशि का व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

7– इस राशि की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–5 / निदे0(मेधावृत्ति)–61–01 / 2014(खण्ड)–के पृ0–64 / टि0 पर प्राप्त है।

8– स्वीकृत राशि योजना उद्व्यय एवं बजट उपबन्ध के अन्तर्गत है।

9– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दिया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्र. सिंह मीणा) 13.2.17

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5 / निदे0(मेधावृत्ति)–61–01 / 2014(खण्ड)– 88 पटना, दिनांक– 13.02.17

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार / सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति / निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उपविकास आयुक्त / सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक,कल्याण / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी / लेखा शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग,–बिहार, पटना / सांख्यिकी कोषांग, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

13.2.17

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5 / निदे0(मेधावृत्ति)–61–01 / 2014(खण्ड)– 88 पटना, दिनांक– 13.02.17

प्रतिलिपि : सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

13.2.17

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–4 / नि0 यो0 छात्र0 163–02 / 2008– 88 पटना, दिनांक– 13.02.17

प्रतिलिपि : आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

13.2.17

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5 / निदे0(मेधावृत्ति)–61–01 / 2014(खण्ड)– 88 पटना, दिनांक– 13.02.17

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

13.2.17

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5 / निदे0(मेधावृत्ति)–61–01 / 2014(खण्ड)– 88 पटना, दिनांक– 13.02.17

प्रतिलिपि : आप्त सचिव, माननीय मंत्री, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

13.2.17

सरकार के सचिव।

allotment-madhubani plan-16-17

विवरणी-1

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजनान्तर्गत मुख्य मंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति मेधावृति योजना (मैट्रिक) में स्वीकृत राशि की विवरणी

क्रमांक	जिला का नाम	प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		कुल अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति	अनु0 जाति के लिए स्वीकृत राशि (विपत्र कोड पी0 2225012770107)	अनु0 जनजाति के लिए स्वीकृत राशि। (विपत्र कोड पी0 2225022770101)	कुल स्वीकृत राशि। (राशि लाख में)
		अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति				
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8
1	पटना	907	30	2313	39	3269	275.74	6.12	281.86
2	नालंदा	1255	12	2864	20	4151	354.62	2.80	357.42
3	रोहतास	662	42	2136	113	2953	237.08	13.24	250.32
4	भभुआ	343	34	920	87	1384	107.90	10.36	118.26
5	भोजपुर	762	38	1819	99	2718	221.72	11.72	233.44
6	बक्सर	151	21	460	88	720	51.90	9.14	61.04
7	गया	1058	18	3762	82	4920	406.76	8.36	415.12
8	जहानाबाद	212	4	739	5	960	80.32	0.80	81.12
9	अरवल	243	9	922	25	1199	98.06	2.90	100.96
10	नवादा	507	11	1784	37	2339	193.42	4.06	197.48
11	औरंगाबाद	750	16	2516	39	3321	276.28	4.72	281.00
12	सारण	523	96	2552	414	3585	256.46	42.72	299.18
13	सिवान	311	106	1148	457	2022	122.94	47.16	170.10
14	गोपालगंज	292	130	1322	469	2213	134.96	50.52	185.48
15	मुजफ्फरपुर	428	23	1654	62	2167	175.12	7.26	182.38
16	सीतामढी	147	2	543	11	703	58.14	1.08	59.22
17	शिवहर	35	0	106	4	145	11.98	0.32	12.30
18	प0 चम्पारण	582	876	1551	1646	4655	182.28	219.28	401.56
19	पू0 चम्पारण	390	21	1299	82	1792	142.92	8.66	151.58
20	वैशाली	485	12	2310	38	2845	233.30	4.24	237.54
21	दरभंगा	394	4	1468	11	1877	156.84	1.28	158.12
22	मधुबनी	519	7	1868	51	2445	201.34	4.78	206.12
23	समस्तीपुर	814	16	2444	46	3320	276.92	5.28	282.20
24	सहरसा	172	5	625	31	833	67.20	2.98	70.18
25	सुपौल	264	8	826	46	1144	92.48	4.48	96.96
26	मधेपुरा	351	33	717	73	1174	92.46	9.14	101.60
27	पूर्णियां	185	82	515	255	1037	59.70	28.60	88.30
28	अररिया	312	18	573	58	961	77.04	6.44	83.48
29	किशनगंज	109	14	224	66	413	28.82	6.68	35.50
30	कटिहार	238	110	879	499	1726	94.12	50.92	145.04
31	भागलपुर	712	136	1197	325	2370	166.96	39.60	206.56
32	बाँका	344	57	921	222	1544	108.08	23.46	131.54
33	मुंगेर	417	25	1060	73	1575	126.50	8.34	134.84
34	लखीसराय	250	9	758	25	1042	85.64	2.90	88.54
35	शेखपुरा	160	0	553	8	721	60.24	0.64	60.88
36	जमुई	254	32	913	146	1345	98.44	14.88	113.32
37	खगडिया	353	26	959	39	1377	112.02	5.72	117.74
38	बेगुसराय	799	9	1824	22	2654	225.82	2.66	228.48
	कुल योग	16690	2092	51044	5813	75639	5752.52	674.24	6426.76

(कुल चौसठ करोड छब्बीस लाख छिहत्तर हजार रु0 मात्र)

पत्रांक-89 दिनांक-13.02.17 का अनुलग्नक ।

सरकार के सचिव
अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग

विवरणी–2

बिहार सरकार

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजनान्तर्गत मुख्य मंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति मेधावृति योजना (इंटर) में स्वीकृत राशि की विवरणी

क्रमांक	जिला का नाम	बालिका					राशि रू० लाख में		
		अनु० जाति		अनु० जन जाति		योग	अनु० जाति (विपत्र कोड–पी02225012770107)	अनु० जनजाति (विपत्र कोड–पी02225022770191)	योग
		I	II	I	II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पटना	361	1132	30	37	1560	167.35	8.20	175.55
2	नालंदा	149	761	0	3	913	98.45	0.30	98.75
3	भोजपुर	51	491	5	28	575	56.75	3.55	60.30
4	बक्सर	32	261	1	42	336	30.90	4.35	35.25
5	रोहतास	71	425	5	25	526	53.15	3.25	56.40
6	भभुआ	43	455	5	43	546	51.95	5.05	57.00
7	गया	141	782	6	17	946	99.35	2.60	101.95
8	जहानाबाद	11	188	0	2	201	20.45	0.20	20.65
9	नवादा	60	510	3	6	588	61.35	1.05	62.40
10	औरंगाबाद	54	601	3	10	668	68.20	1.45	69.65
11	अरवल	51	391	1	5	448	46.75	0.65	47.40
12	मुजफ्फरपुर	389	792	38	36	1255	137.55	9.30	146.85
13	सीतामढ़ी	325	253	16	12	606	74.05	3.60	77.65
14	वैशाली	193	1080	11	14	1298	136.95	3.05	140.00
15	पू० चम्पारण	183	474	15	33	705	74.85	5.55	80.40
16	प० चम्पारण	134	443	413	532	1522	64.40	115.15	179.55
17	शिवहर	37	88	0	34	159	14.35	3.40	17.75
18	सारण	133	996	30	111	1270	119.55	15.60	135.15
19	सिवान	102	553	51	194	900	70.60	27.05	97.65
20	गोपालगंज	60	464	33	176	733	55.40	22.55	77.95
21	दरभंगा	161	677	6	78	922	91.85	8.70	100.55
22	मधुबनी	377	847	12	20	1256	141.25	3.80	145.05
23	समस्तीपुर	230	1162	12	22	1426	150.70	4.00	154.70
24	सहरसा	35	193	3	18	249	24.55	2.25	26.80
25	सुपौल	114	242	14	15	385	41.30	3.60	44.90
26	मधेपुरा	115	422	12	44	593	59.45	6.20	65.65
27	भागलपुर	110	443	39	126	718	60.80	18.45	79.25
28	बाँका	69	287	20	106	482	39.05	13.60	52.65
29	मुंगेर	56	345	7	51	459	42.90	6.15	49.05
30	जमुई	80	377	9	82	548	49.70	9.55	59.25
31	खगड़िया	34	161	0	29	224	21.20	2.90	24.10
32	बेगूसराय	231	763	4	17	1015	110.95	2.30	113.25
33	लखीसराय	20	136	3	4	163	16.60	0.85	17.45
34	शेखपुरा	31	173	2	5	211	21.95	0.80	22.75
35	पूर्णियां	89	247	58	179	573	38.05	26.60	64.65
36	अररिया	143	247	13	29	432	46.15	4.85	51.00
37	किशनगंज	42	88	10	18	158	15.10	3.30	18.40
38	कटिहार	105	387	35	173	700	54.45	22.55	77.00
		4631	18337	925	2376	26269	2528.35	376.35	2904.70

(कुल उनतीस करोड़ चार लाख सत्तर हजार रु० मात्र)

पत्रांक- 58 दिनांक- 15.02.17 का अनुलग्नक।

सचिव
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

4061
16-05-16

बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

संकल्प

विषय :--भारत सरकार एवं राज्य सरकार की प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं विगत वर्षो की बकाया छात्रवृति की राशि के भुगतान तथा प्रतिबद्ध देयता (Committed Liability) के तहत् आगामी वर्षों में नवीकृत छात्रों के पाठ्यकम पूर्ण होने तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृति के लिए दर की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान् छात्र/छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करने के लिए योजना, गैर योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना संचालित है। इस योजना के तहत् विधिवत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/ संस्थान में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को छात्रवृति की स्वीकृति दी जाती है। इस योजना के तहत् राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है।

2. यह योजना राज्य के अंदर एवं बाहर सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से संचालित है।

3. इस योजना के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को मुख्य धारा में शामिल किया जाता है तथा उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य के अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के वैसे छात्र/छात्रा, जिनके माता पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2,50,000/--रू० (दो लाख पचास हजार रू0) तक हो, को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2016–17 से राज्य सरकार के सात निश्चय के अनुपालन में "स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड" (Student Credit Card) के तहत छात्रों को लाभान्वित किया जाना है।

4. राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य के अन्दर एवं बाहर सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानो के लिए शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव विचाराधीन था और राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर के सरकारी शिक्षण संस्थानों तथा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में राज्य के अधिकतम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को लाभ पहुँचाने के लिए शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्कों की छात्रवृत्ति दर की अधिकतम सीमा का निर्धारण करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

5. अतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः–

(I) भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत् निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं विगत वर्षो में राज्य के अन्दर सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों एवं राज्य के बाहर सभी सरकारी एवं मान्यताप्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को संबंधित राज्य के सरकारी संस्थान में निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर पर छात्रवृत्ति की राशि अनुमान्य की जाएगी।

(II) भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के तहत् निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष--2015–16 में एवं इसके पूर्व के वर्षो में राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (अधिकतम सीमा ₹ 15,000/– के अन्तर्गत) पाठ्यकम/कोर्स के अनुसार छात्रवृत्ति की राशि की स्वीकृति निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैः–

क्र0	कोर्स की विवरणी	छात्रवृत्ति की राशि की अधिकतम वार्षिक सीमा (देय शिक्षण शुल्क + अनिवार्य शुल्क या निम्न निर्धारित राशि, दोनों में जो न्यूनतम हो)
1	विभिन्न +2 विद्यालयों / महाविद्यालयों में इंटरमीडियट कक्षा यथा–आई0ए0 / आई0एस0सी0 / आई0कॉम एवं अन्य समकक्ष कोर्स।	₹ 2000 / –
2	स्नातक स्तरीय कक्षा यथा–बी0ए0 / बी0एस0सी0 / बी0कॉम एवं अन्य समकक्ष कोर्स।	₹ 5000 / –
3	स्नातकोत्तर कक्षा यथा–एम0ए0 / एम0एस0सी0 / एम0कॉम / एम0फिल0 / पी0एच0डी0 एवं अन्य समकक्ष कोर्स।	₹ 5000 / –
4	आई0टी0आई0	₹ 5000 / –
5	त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम / पॉलिटेक्नीक एवं अन्य समकक्ष कोर्स।	₹ 10000 / –
6	व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान के अधीन संचालित कोर्स, यथा–इंजीनियरिंग / मेडिकल / विधि / प्रबंधन तथा अन्य समकक्ष कोर्स (कृषि को छोड़कर)।	₹ 15000 / –

(III) केन्द्रीय सरकारी शिक्षण संस्थानों (यथा–आई0आई0टी0 तथा एन0आई0टी0 में अध्ययनरत् छात्र / छात्राओं के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क सहित अधिकतम कमशः ₹ 90,000 / – तथा ₹ 70,000 / – की दर) एवं अन्य केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों यथा–नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एन0आई0एफ0टी0, जे0आई0पी0एम0ई0आर0, ए0आई0आई0एम0एस0 आदि में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क सहित अधिकतम ₹ 75,000 / – की दर पर छात्रवृत्ति अनुमान्य होगी एवं निर्धारित शिक्षण एवं अन्य अनिवार्य शुल्क तथा अधिकतम सीमा में जो न्यूनतम होगा, उसी दर पर भुगतेय होगा।

(IV) मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानो में अध्ययनरत् छात्र / छात्राओं की तुलना में सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत् छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृति में प्राथमिकता दी जाएगी।

(V) अनुमान्य छात्रवृत्ति राशि के अतिरिक्त समय–समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुरक्षण भत्ता भी देय होगा।

6. उपर्युक्त के अनुपालन के क्रम में विहित प्रक्रिया अन्तर्गत सम्यक् जाँचोपरांत संबंधित पदाधिकारी छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

16.5.16

(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-5/निदे0(छात्र0)--23-151/16-- 4061 पटना, दिनांक- 16/05/16

प्रतिलिपि - अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को संकल्प की दो हार्ड प्रतियों एवं [illegible] सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प की 1500 (एक हजार पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

16.5.16
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-5/निदे0(छात्र0)--23-151/16- 4061 पटना, दिनांक-16/05/16

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.5.16
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-5/निदे0(छात्र0)-23-151/16- 4061 पटना, दिनांक- 16/05/16

प्रतिलिपि - सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.5.16
सरकार के सचिव।

सं0–5/निदे0(विज्ञापन–प्रवे0)191–01/2017–798

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

संकल्प

25 मार्च 2017

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 11 वीं एवं 12 वीं वर्ग में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को निर्धारित मापदण्डों के आधार पर छात्रवृति भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान् छात्र/छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करने के लिए योजना, गैर योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना सचालित है। इस योजना के तहत् मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को छात्रवृति की स्वीकृति दी जाती है। इस योजना के तहत् राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है।

2– इस योजना के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को मुख्य धारा में शामिल किया जाता है तथा उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के, वैसे छात्र/छात्राएँ, जिनके माता पिता/अभिभावक की वार्षिक आय ₹2,50,000/– (दो लाख पचास हजार रू0) तक हो, को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

3– वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा निर्गत विभागीय संकल्प सं0–4061 दिनांक–16.05.16 के आलोक में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं विगत वर्षो की बकाया छात्रवृति की राशि के भुगतान तथा प्रतिबद्ध देयता (Committed Liability) के तहत आगामी वर्षो में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृति के लिए दर की अधिकतम सीमा निर्धारित है।

4– अतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 11 वीं एवं 12 वीं कक्षा में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत राज्य के अंदर एवं बाहर के सरकारी शिक्षण संस्थानों तथा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार निर्णय लिया गया है कि "**वित्तीय वर्ष 2016–17 से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 11 वीं एवं 12 वीं वर्ग में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को विभागीय संकल्प सं0–4061 दिनांक–16.05.16 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर छात्रवृति की राशि स्वीकृत की जाएगी।**"

5– उपर्युक्त के अनुपालन के क्रम में विहित प्रक्रिया अन्तर्गत सम्यक् जाँचोपरांत संबंधित पदाधिकारी छात्रवृति की राशि का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

25.3.17

(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 5/निदे0(विज्ञापन–प्रवे0)191–01/2017-798 पटना, दिनांक–25.03.2017

प्रतिलिपि– हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इसे राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभाग को 1500 अतिरिक्त प्रतियां भेजने हेतु अग्रसारित ।

25.3.17
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– 5/निदे0(विज्ञापन–प्रवे0)191–01/2017-798 पटना, दिनाक–25.03.2017

प्रतिलिपि– हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.3.17
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– 5/निदे0(विज्ञापन–प्रवे0)191–01/2017-798 पटना, दिनांक–25.03.2017

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.3.17
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– 5/निदे0(विज्ञापन–प्रवे0)191–01/2017-798 पटना, दिनांक–25.03.2017

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.3.17
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– 5/निदे0(विज्ञापन–प्रवे0)191–01/2017-798 पटना, दिनांक–25.03.2017

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय को सूचनार्थ प्रेषित।

25.3.17
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– 5/निदे0(विज्ञापन–प्रवे0)191–01/2017-798 पटना, दिनांक–25.03.17

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

25.3.17
सरकार के सचिव ।

Sankalp for pms

परि०-4(ख)

CENTRALLY-SPONSORED

SCHEME OF

POST MATRIC SCHOLARSHIPS

TO THE STUDENTS

BELONGING TO

SCHEDULED CASTES

FOR STUDIES IN INDIA

(EFFECTIVE FROM 01-07-2010)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
December, 2010

CENTRALLY-SPONSORED SCHEME OF POST MATRIC SCHOLARSHIPS TO THE STUDENTS BELONGING TO SCHEDULED CASTES FOR STUDIES IN INDIA (EFFECTIVE FROM 01-07-2010)

CONTENTS

Sl. No.	Topic	Page No.
1.	Object	2
2.	Scope	2
3.	Conditions of Eligibility	3-4
4.	Means Test	5
5.	Value of Scholarship	5
	(i) Maintenance Allowance	6-7
	(ii) Additional Allowances for SC students with disabilities	7
	(iii) Fees	8
	(iv) Study Tours	8
	(v) Thesis Typing / Printing Charges	8
	(vi) Book Allowance for Students pursuing Correspondence /Distance Education Courses	9
	(vii) Book Banks	9-10
6.	Selection of Candidates	11
7.	Duration and Renewal of Awards	11
8.	Payment	11-12
9.	Mode of Disbursal of Scholarship	12
10.	Other Conditions for the Award	12
11.	Announcement of the Scheme	13
12.	Procedure for Applying	13
13.	Funding Pattern of the Scheme	13

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

*****

SCHEME OF POST MATRIC SCHOLARSHIPS TO THE STUDENTS BELONGING TO SCHEDULED CASTES FOR STUDIES IN INDIA

(EFFECTIVE FROM 01-07-2010)

I. OBJECT

The objective of the scheme is to provide financial assistance to the Scheduled Caste students studying at post matriculation or post-secondary stage to enable them to complete their education.

II. SCOPE

These scholarships are available for studies in India only and are awarded by the government of the State/Union Territory to which the applicant actually belongs i.e. permanently settled.

III. CONDITIONS OF ELIGIBILITY

(i) The scholarships are open to nationals of India.

(ii) These scholarships will be given for the study of all recognized post-matriculation or post-secondary courses pursued in recognized institutions with the following exceptions:

"Scholarships are not awarded for training courses like Aircraft Maintenance Engineer's Courses and Private Pilot license Courses. Courses at Training – Ship Dufferin (Now Rajendra), courses of training at the Military College, Dehradun, courses at Pre-examination Training Centres of all India and State levels."

(iii) Only those candidates who belong to Scheduled Castes so specified in relation to the State/Union Territory to which the applicant actually belongs i.e. permanently settled and who have passed the Matriculation or Higher Secondary or any higher examination of a recognised University or Board of Secondary Education, will be eligible.

(iv) Candidates who after passing one stage of education are studying in the same stage of education in different subject e.g. I.Sc. after I.A. or B.Com. after B.A. or M.A. in other subject will not be eligible.

(v) Students who, after having completed their educational career in one professional line, e.g. L.L.B. after B.T./B.Ed. will not be eligible. From the academic year 1980-81, studies in two professional courses are allowed.

(vi) Students studying in Class XI of the Higher Secondary School courses of the XII Class of the Multipurpose High School will not be eligible for it being a continuous school course. However, in cases where X^{th} class examination of such courses is treated as equivalent to Matriculation and students who after passing X^{th} class join other courses, such students will be treated as post-matric students and will be eligible for the award of scholarships.

(vii) Students pursuing Post Graduate courses in medicine will be eligible if they are not allowed to practice during the period of their course.

(viii) Students who after failing or passing the under graduate/post-graduate examinations in Arts/Science/Commerce join any recognised professional or Technical certificate/diploma/degree courses will be awarded scholarships if otherwise eligible. No subsequent failure will be condoned except courses in Group 'I'.

(ix) Students who pursue their studies through correspondence courses are also eligible. The term correspondence includes distant and continuing education.

(x) Employed students whose income combined with the income of their parents/guardians does not exceed the maximum prescribed income ceiling are made eligible to post-matric scholarships to the extent of reimbursement of all compulsorily payable non-refundable fees.

(xi) All children of the same parents/guardians will be entitled to receive benefits of the scheme.

(xii) A scholarship holder under this scheme will not hold any other scholarship/stipend. If awarded any other scholarship/stipend, the student can exercise his/her option for either of the two scholarships/stipends, whichever is more beneficial to him/her and should inform the awarding authority through the Head of the Institution about the option made. No scholarship will be paid to the students under this scheme from the date he/she accepts another scholarship/stipend. The student can however, accept free lodging or a grant or adhoc monetary help from the State Government or any other source for the purchase of books, equipment or for meeting the expenses on board and lodging in addition to the scholarship amount paid under this scheme.

(xiii) Scholarship holders who are receiving coaching in any of the pre-examination training centres with financial assistance from the Central Government/ State Government will not be eligible for stipend under the coaching schemes for the duration of the coaching programme.

Note I: It is mentioned under the item III (condition of eligibility) of this scheme that the scholarship will be given for the study of all recognised post-matriculation or post-secondary courses pursued in recognised institutions, the list of courses grouped (I to IV) is only illustrative and not exhaustive. The State Governments/Union Territory Administrations are, thus, themselves competent to decide the appropriate grouping of

courses at their level as advised vide this Ministry's letter No.11017/13/88-Sch.Cell, dated 3.8.1989.

IV. MEANS TEST

Scholarships will be paid to the students whose parents/guardians' income from all sources does not exceed Rs. *2,50,000/- (Rupees two lakh fifty thousand only)* per annum w.e.f. academic session 2013-14.

NOTE 1: So long as either of the parents (or husband in the case of married unemployed girl student) is alive, only income of the parents/husband, as the case may be, from all sources has to be taken into account only and of no other member even though they may be earning. In the form of income declaration, income is to be declared on this basis

Only in the case where both the parents (or husband in the case of married but unemployed girl student) have died, the income of the guardian who is supporting the student in his/her studies has to be taken. Such students whose parent's income is affected due to unfortunate death of one of earning parents and resultantly comes within the income ceiling prescribed under the scheme, shall become eligible for scholarship, subject to their fulfilling other conditions of eligibility, from the month in which such sad incidence takes place. Applications for scholarships from such students can be considered even after lapse of last date of receipt of applications, on compassionate grounds.

NOTE 2: House rent allowance received by the parents of a student shall be exempted from the computation of 'income' if the same has been permitted to be exempted for the purpose of Income tax.

NOTE 3: Income certificate is required to be taken once only i.e. at the time of admission to courses which are continuing for more than one year.

NOTE 4: The revised income ceiling has been further upgraded, after taking into account Consumer Price Index for Industrial workers upto October *2009*. Income Ceiling would be revised once in every two years linking it with Consumer Price Index for Industrial Workers for the month of October of the year, preceding the year of revision and will be made effective from April.

V. VALUE OF SCHOLARSHIP

The value of scholarship includes the following for complete duration of the course:-

(i) ***maintenance allowance,***
(ii) ***reimbursement of compulsory non-refundable fees,***
(iii) ***study tour charges,***
(iv) ***thesis typing/printing charges for Research Scholars,***
(v) ***book allowance for students pursuing correspondence courses,***
(vi) ***book bank facility for specified courses, and***
(vii) ***additional allowance for students with disabilities, for the complete duration of the course.***

The details are as follows:

(i) Maintenance allowance:

Groups		**Rate of Maintenance allowance (in Rupees per month)**	
Group	**Courses**	Hostellers	Day Scholars

Group I	*(i) Degree and Post Graduate level courses in Medicine (Allopathic, Indian and other recognized systems of medicines), Engineering, Technology, Planning, Architecture, Design, Fashion Technology, Agriculture, Veterinary & Allied Sciences, Management, Business Finance /Administration, Computer Science/ Applications.* *(ii) Commercial Pilot License (including helicopter pilot and multiengine rating) course.* *(iii) Post Graduate Diploma courses in various branches of management & medicine.* *(iv) C.A./I.C.W.A./C.S./I.C.F.A. etc.* *(v) M. Phil., Ph.D. and Post Doctoral Programmes (D. Litt., D.Sc. etc.), Group I, Group II and Group III courses* *(vi) L.L.M.*	*1200*	*550*
Group II	*(i) Professional Courses leading to Degree, Diploma, Certificate in areas like Pharmacy (B Pharma), Nursing(B Nursing), LLB, BFS, other para-medical branches like rehabilitation, diagnostics etc., Mass Communication, Hotel Management & Catering, Travel/Tourism/Hospitality Management, Interior Decoration, Nutrition & Dietetics, Commercial Art, Financial Services (e.g. Banking, Insurance, Taxation etc.) for which entrance qualification is minimum Sr. Secondary (10+2).* *(ii) Post Graduate courses not covered under Group I eg. MA/M Sc/M.Com/M Ed./M. Pharma etc.*	*820*	*530*
Group III	*All other courses leading to a graduate degree not covered under Group I & II eg. BA/B Sc/B Com etc.*	*570*	*300*
Group IV	*All post-matriculation level non-degree courses for which entrance qualification is High School (Class X), e.g.senior secondary certificate (class XI and XII); both general and vocational stream, ITI courses, 3 year diploma courses in Polytechnics, etc.*	*380*	*230*

Note 1: Commercial Pilot License Course (CPL)

CPL course would include Commercial Helicopter Pilot License (CHPL) and multi-engine rating training on A-320 and similar aircrafts even after the candidate has got scholarship for multi-engine rating training with the CPL course. CPL course is covered under Group 'I'. The number of awards for CPL will be 50 per annum. Consequent upon receiving applications from concerned students, concerned State Governments/UT Admns. should scrutinize them for determining their eligibility under the scheme and thereafter recommend the number of eligible applicants for CPL training (with their